Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VII, Issue No. XIII, January-2014, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

भ्रष्टाचार और आन्दोलन

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VII, Issue No. XIII, January-2014, ISSN 2230-7540

भ्रष्टाचार और आन्दोलन

Nirmala

Vice Principal, Seth Navrang Ram Manohar Lohiya, Jay Ram Kanya Mahavidhyala, Lohar Majara, Kurukshetra

----------X----------

भ्रष्टाचार तेरे रूप अनेक, दूसरे शब्दो में आज अनेक क्या प्रत्येक स्तर पर और अनेक रूपों में जीवन–समाज में भ्रष्टाचार का विस्तार हो चुका है; निरन्तर होता ही जा रहा है। आज धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, कला, संस्कृति आदि का कोई भी कोना ऐसा नही बचा जहाँ भ्रष्टाचार के कदम न पहुँच पाए हों। कर्मचारी, राजनेता, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, ठेकेदार, साधारण मजदूर, इन्जीनियर, व्यवसायी, उद्योगपति, छोटे दुकानदार यहाँ तक मंदिरों के पुजारी, शिक्षक, गृहस्थ सभी एक दूसरे को अपनी क्षमता से लूटने में लगे हैं। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष व जाति विशेष तक ही सीमित नहीं है अपितु सम्पूर्ण समाज में इस प्रकार संचालित है कि इस विषय में शोषक व शोषित में भेद करना दुष्कर है, क्योंकि जो व्यक्ति एक स्थान पर शोषित है वहीं दूसरे स्थान पर शोषक है। अपने निजी स्वार्थों के कारण एक व्यक्ति एक स्थान पर भ्रष्टाचार का आलोचक है वहीं दूसरे स्थान पर भ्रष्टाचार का पोषक है किन्तु वास्तव में भ्रष्टाचार एक आलोचय विषय है व इसके विज्ञान और सभ्यता में बढ़ते चरण जहां मानव जीवन के लिए सुख व सुविधा के नवीनतम साधन खोजते हैं वहीं मानव–मानव के बीच की खाई को भी अधिक गहरा बनाते हैं। ये सुख–साधन हमारे अन्दर राष्ट्रीय स्तर व अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं जिन्हे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है। इसका मूल कारण है असीमित आवश्यकताएं व सीमित साधन और इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अवांछनीय कार्यों में संलिप्त हो जाता है। जिससे अमीर व गरीब के बीच की खाई ओर चौड़ी हो जाती है। पूंजीपति व्यक्ति अपनी प्रसिद्धी व धन को ओर अधिक बढ़ाने के लिए काला धन जमा करने लगता है और गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के निवारण के लिए गलत कामों जैसे– चोरी, डकैती आदि बुरे कामों में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार इन सुख–सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हम अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति को Ðास पहुँचाकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर काफी बढ़ चुके हैं। पाश्चात्य संस्कृति साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की उपयुक्तता विचार नही करती है और 'सब चलता है' कि मनोवृति का विकास करती है। यह मनोवृति मनुष्य के उचित अनुचित की समझ व आवश्यकता दोनो को समस्तर पर ला खड़ा करती है और मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है।

आज भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या तो है ही किन्तु भारत में यह बिमारी कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चली है, हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ, 2–जी स्पेक्ट्रम व आदर्श घोटालों के पर्दाफाश होने से यह साबित हो गया कि राजनीतिज्ञों आर भ्रष्टाचार का चोली –दामन का साथ हो चुका है और देश ने यदि जल्द ही कोई उपसय नहीं किए तो भारत को विश्व पटल पर शक्तिशाली और विकसित देश बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। राजनैतिकक, प्रशासनिक और अपराधिक गठजोड़ भ्रष्टाचार में वृदि के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। साथ ही लोगों की अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्तता स्थिति की ओर भी गंभीर बनाती है अनेक राज्यों की सरकारों के घोटालों का पर्दाफाश होता है। लोकतांत्रीक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चकी है कि

www.ignited.in

उन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शिक्षक जैसे पवित्र वर्ग को भी भ्रष्ट कर दिया। सरकारें नियुक्ति के नाम पर व शिक्षकों की भर्ती के नाम पर लाखों रूपया रिश्वत लेती है व भाई–बंधुता, क्षेत्रवाद व सम्बन्धवाद जैसे कृत्यों को बढ़ावा देती है। जो शिक्षक स्वयं रिश्वत व सिफारिश के बल पर नियुक्त हुए हों वे एक अच्छे भावी नागरिक कैसे तैयार कर सकते है। ऐसे ही वकील जैसे पेशेवर व्यक्ति चन्द रूपयों के लालच में झूठे मामलों को न्यायलय में सच साबित कर देते है जिससे पूंजीपति भ्रष्ट व्यक्ति ज्यों के त्यों दूध के धूले हुए साफ–सुथरे रहते है और सच्चाई झूठ के आगे दब जाती है।

आजकल दुनिया के लगभग हर इंसान की जुबान पर बस एक ही प्रश्न छाया हुआ है – "भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए?" प्रतिदिन के समाचार पत्रों के पन्ने हों या अन्य समाचार माध्यम हो इसी विषय पर चर्चा करते नज़र आते हैं।

इतिहास गवाह है कि दुनिया में जो परिवर्तन, बदलाव और क्रांतियां हुई हैं उनमें छात्रों तथा युवाओं की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। अगर सुभाष चन्द्र बोस केवल यह सोचते कि मुझे तो आई.ए.एस. की परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी करनी है देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नही करना तो शायद ही हमारा देश आजाद होता। यदि गांधी जी भी ऐसा सोचते कि विदेश से वकालत की शिक्षा ग्रहण करके अच्छी वकालत करनी है तो देश में आजादी के आंदोलन न होते। उस समय लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया था बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे यह समस्या अग्रेजों की व्यवस्था के समय में भी आनदोलन का विषय बनी हुई थी। इन्ही आन्दोलनों व क्रांतियों के कारण ही आज अन्ना हजारे जैसे सत्यग्रही व युवा पिढ़ी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन करने की प्रेरणा व जोश मिला। आज भी बहुत लोगों ने भ्रष्टाचार से त्रस्त हो कर सरकारी नौकरियों को दाव पर लगा कर आंदोलन में बढ़–चढ़कर भाग लिया था।

अगर यह विषय सिरे से चढ़ता है और भ्रष्टाचार के विरूद्ध कोई खास कानून बनकर देश के सामने आता है तो सच मानिए कि भारत का वर्तमान तो सुखद होगा ही भविष्य भी खुशहाल हो सकेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर देशवासी असमंजस में है कि जिस सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने का जिम्मा है वह इस सम्बन्ध में कोई असरदार कानून बनाएगी? अगर लोकपाल कानून बन गया तो सरकार पर भी नजर रखी जा सकेगी। भ्रष्टाचार के दायरे में सभी को आना चाहिए चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायधीश। लेकिन लगता है कि सख्त लोकपाल कानून की बात सपना बन कर ही रह जाएगी, सरकार के वर्तमान रुख से तो ऐसा ही लगता है परन्तु भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है, जिसका समाधान होना ही चाहिए। इसके लिए देश भर में भ्रष्टाचार के विरूद्ध चल रहे अलग–अलग आन्दोलनों को संगठित होना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के बने रहने से युवाओं का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए युवाओं को इसके विरूद्ध आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। हमारे देश में आज एक वर्ग भ्रष्टाचार को लेकर आन्दोलित है वहीं समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आन्दोलन में नही है ये कटु सत्य है जिसे हमें मानना होगा। परन्तु ऐसा नही है कि ये वर्ग भ्रष्टाचार से त्रस्त नही है और शायद सबसे ज्यादा परन्तु यह वर्ग आन्दोलन की सफलता को लेकर असमंजस में है।

भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसे किसी खास दल, वर्ग समूह या व्यक्ति से जाड़ कर नही देखा जा सकता और न ही सिर्फ कानून बनाने से खत्म होगा क्योंकि कानून तो पहले भी व्याप्त है फिर भी समाज में बुराइयाँ ज्यो की त्यों बनी हुई हैं सख्त कानून के साथ हमें सामाजिक जागृति की भी जरुरत है

कहाँ-कहाँ है भ्रष्टाचार

वैसे तो भ्रष्टाचार ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा हैपर यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो ये सबसे ज्यादा ऊपर के स्तर पर मौजूद दीखता है.पिछले काफ़ी अरसे से देश की जनता भ्रष्टाचार से जूझ रही है और

www.ignited.in

भ्रष्टाचारी मज़े कर रहे हैं. पंचायतों से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है. सरकारी दफ़्तरों के चपरासी से लेकर आला अधिकारी तक बिना रिश्वत के सीधे मुंह बात तक नहीं करते. संसद के अन्दर भ्रष्टाचार को लेकर हौ-हल्ला होता है तो बाहर जनता धरने-प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इज़हार करती है. हालांकि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर भी तमाम दावे कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है, लेकिन नतीजा वही 'ढाक के तीन पात' ही रहता है. अब तो हालत यह हो गई है कि हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में भी लगातर तरक्क़ी कर रहा है. विकास के मामले में भारत दुनिया में कितना ही पीछे क्यों न हो, मगर भ्रष्टाचार के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गया है.

गौरतलब है कि जर्मनी के बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल भारत में काम कराने के लिए 54 फ़ीसदी लोगों को रिश्वत देनी पड़ी. जबकि पूरी दुनिया की चौथाई आबादी घूस देने को मजबूर है. इस संगठन एनजीओ ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में दुनियाभर के 86 देशों में 91 हज़ार लोगों से बात करके रिश्वतखोरी से संबंधित आंकड़े जुटाए हैं. 2010 के ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के मुताबिक़ पिछले 12 महीनों में हर चौथे आदमी ने 9 संस्थानों में से एक में काम करवाने के लिए रिश्वत दी. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग से लेकर अदालतें तक शामिल हैं.

भ्रष्टाचार के मामले में अफ़गानिस्तान,नाइजीरिया इराक़ और भारत सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों की फ़ेहरिस्त में शामिल किये गए हैं.इन देशों में आधे से ज़्यादा लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में 74 फ़ीसदी लोगों का कहना है कि देश में पिछले तीन बरसों में रिश्वतखोरी में ख़ासा इज़ाफ़ा हुआ है, बाक़ी दुनियाभर के 60 फ़ीसदी लोग ही ऐसा मानते हैं. इस रिपोर्ट पुलिस विभाग को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट करार दिया गया है. पुलिस से जुड़े 29 फ़ीसदी लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी है. संस्था के वरिष्ठ अधिकारी रॉबिन होंडेस का कहना है कि यह तादाद पिछले कुछ सालों में बढ़ी है और 2006 के मुक़ाबले दोगुनी हो गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन (79वें), भारत (84वें), पाकिस्तान और बांग्लादेश (139वें) में भ्रष्टाचार तेज़ी से फैल रहा है. हालत यह है कि धार्मिक संगठनों में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है.क़ाबिले-गौर है कि ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल 2003 से हर साल भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रही है. वर्ष 2009 की रिपोर्ट में सोमालिया को सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है, जबकि इस साल भारत इस स्थान रहा है. देश में पिछले छह महीनों में आदर्श हाउसिंग घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों में धांधली, और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है. जब ऊपरी स्तर पर यह हाल है तो ज़मीनी स्तर पर क्या होता होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

टीआई की रिपोर्ट में न्यूज़ीलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन और स्विटज़रलैंड को दुनिया के सबसे ज़्यादा साफ़-सुथरे देश बताया गया है. गौरतलब है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय सचिवालय बर्लिन में स्थित है और दुनियाभर के 90 देशों में इसके राष्ट्रीय केंद्र हैं. विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का स्तर मापने के लिए टीआई दुनिया के बेहतरीन थिंक टैंक्स, संस्थाओं और निर्णय श्रमता में दक्ष लोगों की मदद लेता है. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट की ओर से घोषित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौक़े पर जारी की जाती है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल की 191 देशो की फ़ेहरिस्त में भारत को 178वें स्थान पर रखा गया था. करेप्शन प्रेसेप्शन इंडेक्स में भारत 87 वें पायदान पर है. संसद में बैठे नेताओं में से क़रीब एक चौथाई पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं. 1948 से 2008 तक अवैध तरीक़े से हमारे देश से क़रीब 20 लाख करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं, जो देश की आर्थिक विकास दर (जीडीपी) का चालीस फ़ीसदी है.

विभिन्न संगठनों के संघर्ष के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को देशभर में सूचना का अधिकार क़ानून भी लागू किया गया. इसके बावजूद रिश्वत खोरी कम नहीं हुई. अफ़सोस तो इस बात का है कि भ्रष्टाचारी ग़रीबों, बुजुर्गों और विकलांगों तक से रिश्वात मांगने से बाज़ नहीं आते. वृद्धावस्था पेंशन के मामले में भी भ्रष्ट अधिकारी लाचार बुजुर्गों के आगे भी रिश्वत के लिए हाथ फैला देते हैं

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार की तरफ़ से जारी एक रुपए में से जनता तक सिर्फ़ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं. ज़ाहिर है बाक़ी के 85 पैसे सरकारी अफ़सरों की जेब में चले जाते हैं. जिस देश का प्रधानमंत्री रिश्वतखोरी को स्वीकार कर रहा हो, वहां जनता की क्या हालत होगी

कहने की ज़रूरत नहीं. मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मानते हैं कि मौजूदा समय में देश में भ्रष्टाचार और गरीबी बड़ी समस्याएं हैं. हक़ीक़त में जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं का फ़ायदा तो नौकरशाह ही उठाते हैं. आख़िर में जनता तो ठगी की ठगी ही रह जाती है. शायद यही उसकी नियति है.

भ्रष्टाचार वृद्धि के कारण एवं समाधान

भ्रष्टाचार का अर्थ- भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण या पतित व्यवहार। स्वार्थ में लिप्त होकर कोई भी किया गया गलत कार्य भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का दायरा विशाल है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं- रिश्वत'कमीशन लेना, काला बाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट, कर्तव्य से भागना, चोर-अपराधियों को सहयोग करना, अतिरिक्त गलत कार्य में रुचि लेना आदि सभी अनुचित कार्यों को भ्रष्टाचार कहा जायेगा।

भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति- दुर्भाग्य से भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वैसे देखा जाए तो सारे विश्व में भ्रष्टाचारी राक्षस का आतंक फैला हुआ है। भारत के सारे प्रशासनिक से लेकर शैक्षिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का राज चलता है।राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार- आज कल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजनैतिक क्षेत्र में हो रहा है। मंत्रियों को अमीर एवं धनी व्यक्तियों से धन लेकर अपराधियों को देना पड़ता है। ताकि वे चुनाव जीत जाएँ। फलस्वरूप चुनाव जीतने के बाद और व्यक्तियों की स्वार्थ पूर्ण शर्त पूरी हो जाती है।

शैक्षिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार- शैक्षिक क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। अध्यापक के पास जो छात्र ट्यूशन लेते हैं, उन्हें परीक्षा में ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ने में अच्छा हो, उसे कम अंक मिलते हैं।

नौकरी और डिग्रियों के लिए भी रिश्वत लेकर दी जाती है।

चिकित्सा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार- पैसे वाले आदमी एवं अमीर व्यक्तियों का इलाज पहले किया जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति का चाहे जितनी बड़ी उसकी बीमारी हो, उसकी अवहेलना की जाती है। दवाइयों में मिलावट की जाती है, जो रोगी के लिए बहुत खतरनाक होता है।

धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार- धार्मिक क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। हर किसी को मंदिर जाने से पहले पैसे लेकर जाना पड़ता है, पुजारी की साधन दक्षिणा के लिए।

व्यापार के क्षेत्र में भ्रष्टाचार- खाद्य पदार्थों से लेकर प्रत्येक चीज में मिलावट हो रही है, किसी में ईंट तो किसी में रेत मिला हुआ होता है। सीमेंट में भी ज्यादा रेत मिलाकर कमजोर गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं। सभी प्रकार से कार्यालय में भी रिश्वत से ही काम होता है।

भ्रष्टाचार वृद्धि के कारण- समाज में भ्रष्टाचार वृद्धि के कारण तो अनेक हैं, उनमें से कुछ मुख्य कारण हैं-

धन को सम्मान- आजकल अमीर आदमियों का ही समाज में सम्मान है। सच्चरित्र व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसके पास धन नहीं होता है। इसलिए सच्चरित्र व्यक्ति भी भ्रष्टाचार अपनाने लगा है।

धन कमाने की तृष्णा- धन की तृष्णा में जलता हुआ आदमी बाहरी साज-सज्जा के लिए, भोग विलास के लिए पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए सबसे लघुतम साधन है, भ्रष्टाचार। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि वह भ्रष्टाचार फैलाकर दुनिया भर की सम्पत्ति अपने पेट में, मुँह में, घर में भर लेना चाहता है।

भ्रष्टाचार का और एक मुख्य कारण है- भूख एवं गरीबी

भूख एवं गरीबी के कारण व्यक्ति नाम न मिलने पर आदर्श को समान न रखते हुए दहेज जैसी समस्या से संघर्ष करने के लिए भ्रष्टाचार को अपना लेता है।

बेकारी की समस्या के कारण शिक्षित व्यक्ति को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, तो वह विचारा कौन सा रास्ता अपनाएगा। दर-दर की ठोकरें खाने के पश्चात शिक्षित आदमी भी भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाने की बात सोचते हैं। भारत को विकसित देश नहीं बनने देगा भ्रष्टाचार का घुन

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर केपीएमजी की सर्वे रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों ने कहा है भ्रष्टाचार से विकास दर पर बेहद

नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत निवेश घटेगा और पूंजी बाजार को गहरी चोट पहुंचेगी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कंपीटीटिवनेस इंडेक्स-2010 के मुताबिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पद्र्धा बनी रहे इसलिए व्यापार, कारोबार, राजकोषीय और सरकारी खर्च में खुलेपन के साथ-साथ भ्रष्टाचार से मुक्त माहौल भी जरूरी है। भ्रष्टाचार भारत की विकास की रफ्तार को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बिजनेस कंस्ल्टेंसी कंपनी केपीएमजी ने हाल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़े अपने हाल के

सर्वे में कंपनियों के सीईओ, चेयरमैन, कंपनी सेक्र टेरियों, मैनेजरों और कानूनी सलाहकारों को शामिल किया है।

इनमें से दो तिहाई से ज्यादा की राय है कि अगर भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हासिल कर लिया जाए तो नौ फीसदी से ज्यादा विकास दर हासिल की जा सकती है। एक अंतरराष्ट्रीय शोध (इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन एफडीआई इनफ्लो, केटो जर्नल. वॉल्यूम.29 स्प्रिंग-समर, 2009) के मुताबिक भ्रष्टाचार में एक फीसदी की बढ़ोतरी से प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 11 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

उदारीकरण से बढ़ा है भ्रष्टाचार

सर्वे मे 90 फीसदी लोगों ने माना कि भ्रष्टाचार की वजह से शेयर बाजार के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ता है। लगभग 40 फीसदी लोगों ने माना कि बाजार के उतार-चढ़ाव में इसकी भूमिका होती है। सर्वे के मुताबिक 32 फीसदी का मानना था कि भ्रष्टाचार संस्थागत निवेशकों को दीर्घावधि के निवेश से रोकता है। वाशिंगटन स्थित ग्लोबल फाइनेंशियल इंटग्रिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से टैक्स चोरी, अपराध और भ्रष्टाचार के जरिये 1948 से लेकर 2008 तक यानि 60 साल में 462 अरब डॉलर देश से बाहर ले जाया जा चुका है।

रिपोर्ट एक और चौंकाने वाले तथ्य का उजागर करती है। इसके मुताबिक कुल काले धन का 68 फीसदी 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद जमा किया गया है। साफ है कि मुक्त अर्थव्यवस्था और कायदे-कानूनों को ज्यादा उदार बनाने के बाद से विदेश में काला धन जमा करने की रफ्तार बढ़ी है। दरअसल भारत की विकासशील से विकसित देश बनने की दिशा में भ्रष्टाचार एक बड़ी अड़चन है।

भ्रष्टाचार की वजह से बड़ी तादाद में उद्योग समूह बराबरी के मौके के हक से महरूम हो रहे हैं। रिश्वत देकर कम काबिल उद्योग संगठन परियोजनाएं हासिल कर रहे हैं। लेकिन उनकी अक्षमताओं की वजह से परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है। सर्वे से यह साफ हो गया है कि कई मामलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में निजी सेक्टरों का हाथ रहा है। केपीएमजी इंडिया के धोखाधड़ी से जुड़े 2010 के सर्वे के मुताबिक 31 फीसदी लोगों ने कहा उद्योग संगठन कारोबार हासिल करने के लिए रिश्वत देते हैं।

रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम सबसे भ्रष्ट

जिस उद्योग में जितने पक्ष होंगे, उनमें भ्रष्टाचार की संभावना भी उतनी ही होगी। केपीएमजी सर्वे के मुताबिक 50 फीसदी लोगों, कंपनियों और एजेंसियों ने रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की आशंका जताई। इसके बाद सामाजिक विकास से जुड़े सेक्टर थे। इन सेक्टरों में सरकार और राजनीतिक नेताओं का काफी हस्तक्षेप है। इनमें बड़ी पंूजी का निवेश होता है।

परियोजनाओं के लिए कई स्तरों पर अनुमति की जरूरत होती है। प्रक्रियाएं जटिल हैं। परियोजनाओं का आकार विशाल होने की वजह से भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है। वर्ल्ड बैंक की डुइंग बिजनेस रिपोर्ट-2010 के मुताबिक में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 60 से 80 फीसदी भवन परियोजनाएं (कंस्ट्रक्शन) सही तरीके की अनुमति लिये बगैर शुरू कर दी जाती हैं। सार्वजनिक भ्रष्टाचार का यह एक बड़ा उदाहरण है।

जटिल प्रक्रिया बढ़ाती है रिश्वतखोरी

भारत सरकार 2012 से 2017 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर एक खरब डॉलर खर्च करेगी। इसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बड़ी भागीदारी होगी। लगभग 30 फीसदी खर्च पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिये जुटाया जाएगा। देश के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरक्की का बड़ा हाथ होता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का स्तर भी ज्यादा होता है। इसकी वजहें हैं।

इन परियोजनाओं के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के दौरान बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी होती है। वर्ष 2010 में केपीएमजी के धोखाधड़ी से जुड़े सर्वे में इस सेक्टर से जुड़ी कई कंपनियों ने कहा कि रिश्वत देने का अहम मकसद प्रशासनिक अनुमति लेना रहा। दरअसल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को खोल देने से इसमें निवेश करने वालों की भीड़ लग गई है।

हर कोई इसमें हिस्सेदारी चाहती है। कई अनुभव कंपनियां भी इस सेक्टर में कूद पड़ी हैं। अब परियोजनाएं कम हैं और इसमें निवेश करने वाले ज्यादा। ऐसे में रिश्वत के जरिये परियोजना हथियाने वालों की तादाद बढ़ गई है। भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह परियोजनाओं के ठेक हासिल करने की जटिल प्रक्रिया। पर्यावरण क्लीयरेंस, मल्टीपल वेंडर एग्रीमेंट और नियामक एजेंसियों के मानक पर खरा

उतरने की जरूरत की वजह से यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप और न्याय में देरी

केपीएमजी के सर्वे में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरियों और कानूनी सलाहकारों का मानना है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने में सरकार का रिकार्ड काफी खराब रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप और न्याय में देरी की वजह से फैसलों का असर खत्म हो जाता है।

सर्वे में जिन लोगों से राय ली गई है, उनमें से अधिकतर मानते हैं कि मौजूदा और आने वाले कानूनों के बावजूद भ्रष्टाचार बना रहेगा। सूचना के अधिकार के अलावा लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रस्तावित राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक कदमों और कॉरपोरेट गवर्नेंस के निर्देशों के बावजूद अगर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है तो इसकी बड़ी वजह रजनीतिक हस्तक्षेप और न्याय में देरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम नीचे गए हैं। 2009 के सर्वे में भारत 84वें स्थान पर था। लेकिन 2010 में यह 87वें स्थान पर आ गया। जबकि चीन 78वें और ब्राजील 69वें स्थान पर है।

कड़ी सजा, भारी जुर्माने और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के स्टैंड से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। चीन में भ्रष्टाचार के मामले में हर्जाने और जुर्माने की राशि काफी बड़ी है। साथ ही भ्रष्टाचार के दोषियों को मौत की सजा भी मिल सकती है। चीन के कानून में सरकारी अधिकारियों को अपनी आय और संपत्ति को सार्वजनिक करना जरूरी है।

बढ़ती फ़ैशन

आजकल प्रत्येक आदमी फैशन को रहन-सहन का उच्च स्तर समझ लिया है कि जब तक कि हम फैशन में नहीं रहिंगे तो अगला आदमी सोचेगा कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं हैं ।

सामाजिक भ्रस्टाचार

हमारी समाज में आजतक कि सभ्यता रही है कि अपनों से बडों का हमेंशा हमलोगों को आदर करना चाहिए,लेकिन आज के बच्चे तथा सभी मानव जाति अपनी सभ्यता को धीरे-धीरे खोते जा रहें हैं और विदेशी सभ्यता को अपनाते जा रहें हैं। आज के बच्चे चाहते हैं कि हम विदेशी सभ्यता के अनुसार ये अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।आजकल के सभी लड़के ,लड़कियां,महिलायें और पुरुषों चाहते हैं कि हम अपने आप में कितना ज्यादा अधिक से अधिक सुंदर लगे यही सोच आजकल के सभी मानव जाति का हैं।

भ्रष्टाचार का समाधान- समाज से भ्रष्टाचार को दूर करने का सबसे सरल साधन है-

जन चेतना। बच्चों को विद्यालय, घर एवं गुरुजनों से अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, जिससे कि वह भ्रष्टाचार और सदाचार में अंतर समझ सकें और आगे चलकर सदाचार को अपनायें।

सरकारी अधिकारियों के विवेकाधिकार को सीमित करने से भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

अगर ऊँचे पद के अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो छोटा कर्मचारी भी नहीं करेगा।

जन आंदोलन से भी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है।

सरकार भी भारत देश में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए जन आंदोलन से जागृत होकर जनलोकपाल बिल पर अमल कर रही है, जिससे की देश से भ्रष्टाचार कम हो जाए।

सरकारी अधिकारी या मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई भी मामला दर्ज होता है, तो तीन माह के अंदर उन्हें अपने आपको सच्चा प्रमाणित करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें दंड दिया जायेगा।

पुलिस, आर. टी. आई. क़ानून से भी सरकार भ्रष्टाचार को कम करने में सफल हो सकेगी।

इन सभी समाधानों के अलावा सबसे अच्छा एवं सक्रिय समाधान यह है कि अगर राजा एवं प्रजा दोनों सचेत हो जाएँ तथा सच्चे सदाचार को अपना लें, तो भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जायेगा। जनता एवं सरकार दोनों को जागृत होना पड़ेगा।

कहा जाता है- यथा राजा तथा प्रजा, इस तरह समाज से भ्रष्टाचार दूर हो कर सदाचार पनप सकता है।

लेकपाल बिल के अलावा भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। मौजूदा व्यवस्था में भी कईं संस्थाएँ जिनके पास भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर कार्यवाई करने का अधिकार है–

पुलिस– ज्यादातर राज्यों में पुलिस डिपार्टमैंट में एक विशेष 'एंटी करप्शन सेल' होता है। पुलिस के पास यह अधिकार है कि अगर किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सही प्रतीत होती है तो एफ. आई.आर. दर्ज कर सकती है हालांकि उसके बाद उसे संबंधित सदन के अध्यक्ष/पिठासीन पदाधिकारी को सूचित करना जरूरी है।

राज्य सर्तकता आयोग– हर राज्य में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार राज्य के मंत्रीयों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग– केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सर्तकता मामलों ओर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए यह सर्वोच्च संस्था है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.)– यह भ्रष्टाचार और पब्लिक ऑफिस के दुरूपयोग मामलों को देखने के लिए मुख्य एजेंसी है। जहाँ केन्द्रीय सर्तकता आयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ी बातें देखता है वहीं सी.बी. आई. भ्रष्टाचार के मामलों के आपराधिक पहलुओं की जांच करती है।

अतः स्पष्ट है कि पहले से कानून मौजूद है सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि उन्हे सख्ती व इमानदारी से लागू किया जाए। भ्रष्टाचार हमारे बीच में से शुरू होता है। हम अक्सर अपने आस पास इस फलते फूलते देखते है। बल्कि स्वयं भी किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा बन जाते है। अतः सबसे पहले तो हमे अपने अंदर के भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। शुरूआत अपने से और अपनो से हो तभी भ्रष्टाचारी दानव समाप्त हो सकता है। भ्रष्ट नेता व अधिकारी हमारे बीच में से ही आते हैं। किसी लेखक ने इन पंक्तियों में कहा है–

यह भ्रष्टाचार ऐसे, जैसे थी अंग्रेजी सरकार
जिसका था महात्मा ने बदला आकार।

आज चले सब इस पथ करने सपने साकार,
अब भी देरी नहीं हुई है जरूर मिटेगा यह भ्रष्टाचार।।